

## परिवार पहचान पत्र (PPP)

### चर्चा में क्यों?

हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण ने परिवार पहचान पत्र संबंधी डाटा साझा करने के संबंध में सख्त नयिम जारी किये।

- ये नए वनियिम उन शर्तों को परभाषित करते हैं जिनके अंतर्गत **पारिवारिक सूचना डाटा भंडार से पारिवारिक जानकारी को** व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करते हुए सरकारी संस्थाओं के साथ साझा किया जा सकता है।

### मुख्य बढि

- **डाटा साझा करने का उद्देश्य** : साझा किये गए डाटा का उपयोग केवल सरकारी कार्यक्रमों, भर्ती सत्यापन और सार्वजनिक सेवा लाभों के लिये किया जा सकता है।
- **प्रतिबंधित डाटा साझाकरण** : डाटा केवल 'पात्र राज्य संस्थाओं' के साथ साझा किया जा सकता है, जिसमें केंद्र सरकार, हरियाणा राज्य सरकार, वैधानिक प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, बोर्ड, नगिम और अन्य सरकार-नियंत्रित एजेंसियाँ शामिल हैं।
- **पारिवारिक पहचान: प्रत्येक परिवार को आठ अंकों की पारिवारिक पहचान मिलेगी, जो जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण-पत्र जैसे आवश्यक अभिलेखों से जुड़ी होगी।**
  - जब भी कोई जीवन घटना जैसे जन्म, मृत्यु या विवाह घटित होगी, तो परिवार आईडी स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगी।
- **सरकारी योजनाओं के साथ एकीकरण**: डाटा बेस को छात्रवृत्ति, सबसिडी और पेंशन सहित विभिन्न स्वतंत्र योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे लाभार्थी चयन में स्थिरता और सटीकता सुनिश्चित होगी।
- **स्वचालित लाभार्थी चयन**: PPP डाटा बेस में डाटा पात्रता का निर्धारण करेगा, जिससे सरकारी लाभों के लिये स्वचालित स्व-चयन की अनुमति मिलेगी।
- **बार-बार दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता समाप्त**: एक बार प्रमाणीकरण और सत्यापन हो जाने के बाद, लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के लिये अलग-अलग दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट: पीपीपी पहल **डिजिटल गवर्नेंस** की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका उद्देश्य हरियाणा के नवासियों के लिये सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच को सरल बनाना है।